

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और भारत

प्रलिस के लिये:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, क्वाड, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ।

मेन्स के लिये:

रूस-यूक्रेन संघर्ष, भारत के हतियों पर देशों की नीतियों एवं राजनीतिका प्रभाव, महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने 'जनिवा' में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मतदान में हसिसा नहीं ललया । इस परिषद ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों की जाँच के ललये एक अंतरराष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव पेश कलया है ।

- यह कदम इस मायने में महत्त्वपूर्ण है कलथह मतदान 'क्वाड' देशों के साथ भारत की बैठक के बाद हुआ था ।
- भारत ने इससे पूर्व [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) और [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद](#) में भी इसी तरह के प्रस्तावों के संबंध में मतदान में हसिसा नहीं ललया था ।
- भारत ने '[अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी](#)' (IAEA) के प्रस्ताव में भी हसिसा नहीं ललया है, जो चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेरनोबल सहलत कई परमाणु अपशषलट स्थलों पर सुरक्षा से संबंधलत था, कल्योंकल रूसलथों ने उन पर नयलंतरण कर ललया था ।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद:

परचलय:

- मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी नकलया है जो दुनलया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मज़बूत करने हेतु ज़मलमेदार है ।

गठन:

- इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कलया गया था । इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान ललया था ।
- मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय (OHCHR) मानवाधिकार परिषद के सचवलालय के रूप में कार्य करता है ।
- OHCHR का मुख्यालय **जनिवा, स्वलटज़रलैंड** में स्थलत है ।

सदस्य:

- इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मललकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा चुने जाते हैं ।
 - संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण में भागीदार राज्यों के योगदान के साथ-साथ इस संबंध में उनके द्वारा की गई स्वैच्छकल प्रतज्जलाओं और प्रतबलद्धताओं को भी ध्यान में रखता है ।
- परिषद की सदस्यता समान भौगोलकल वतलरण पर आधारलत है । इसकी सीटों का वतलरण नमलनलखलतल प्रकार से कलया गया है:
 - अफ़रीकी देश: 13 सीटें
 - एशालया-प्रशांत देश: 13 सीटें
 - लैटनल अमेरकलकी और कैरेबलनलन देश: 8 सीटें
 - पश्चलमी यूरोपीय और अन्य देश: 7 सीटें
 - पूर्वी यूरोपीय देश: 6 सीटें
- परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और लगातार दो कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुन: चुनाव के ललये पात्र नहीं होता है ।

प्रक्रलया और तंत्र:

- **सार्वभौमकल आवधकल समीक्षा:** [सार्वभौमकल आवधकल समीक्षा](#) (Universal Periodic Review- UPR) यूपीआर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थलतलथियों के आकलन का कार्य करता है ।
- **सलाहकार समतलतल:** यह परिषद के "**थकल टैक**" के रूप में कार्य करता है जो इसे वषलयगत मानवाधिकार मुद्दों पर वषलषज्जता और सलाह

प्रदान करता है।

- **शिकायत प्रक्रिया:** यह लोगों और संगठनों को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परषिद के ध्यान में लाने की अनुमति देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया:** ये विशेष प्रतविदक, विशेष प्रतनिधियों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और कार्य समूहों से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों में वषियगत मुद्दों या मानव अधिकारों की स्थितियों की नगिरानी, जाँच करने, सलाह देने और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य करते हैं।

■ मुद्दे:

- **सदस्यता से संबंधित:** कुछ आलोचकों के लिये परषिद की सदस्यता की संरचना एक महत्त्वपूर्ण चिंता का वषिय रही है, जिसमें कभी-कभी ऐसे देश भी शामिल होते हैं जिनमें व्यापक मानवाधिकार हनन करने वाले देश के रूप में देखा जाता है।
 - चीन, क्यूबा, इरटिरिया, रूस और वेनेजुएला जैसे देश मानवाधिकारों के हनन के आरोप के बावजूद इस परषिद में शामिल हैं।
- **असंगत फोकस:** ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में अमेरिका 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परषिद' से बाहर हो गया था, क्योंकि उसका मानना था कि परषिद द्वारा इज़रायल के वरिद्ध असंगत रूप से कार्य किया जा रहा है, ज्ञात हो कि परषिद ने इज़रायल के वरिद्ध अब तक सबसे अधिक संख्या में प्रस्ताव पारित किये गए हैं।
 - अमेरिका फिर से संगठन में शामिल हो गया है।

■ भारत और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परषिद:

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के विशेष प्रतविदकों के एक समूह द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना 2020 के मसौदे पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है।
- वर्ष 2020 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) प्रक्रिया के तीसरे दौर के हसिसे के रूप में अपनी मध्यवधरिपोर्ट परषिद के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- भारत 1 जनवरी 2019 से तीन साल की अवधि के लिये परषिद के लिये चुना गया था।

Q. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2011)

1. शकिषा का अधकिार
2. सार्वजनकि सेवा तक समान पहुँच का अधकिार
3. भोजन का अधकिार

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतरगत उपरोक्त में से कौन सा/से मानव अधकिार है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टू